रवि कपूर

बनाम

राजस्थान राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 1838)

16 अगस्त, 2012

[स्वतंत्र कुमार और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस.279, 337, 338 और 304 ए-मोटर दुर्घटना के तहत अभियोजन-जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं और कई लोग घायल हुए-घटना के प्रत्यक्षदर्शी —गवाहों द्वारा पहचाने गए चालक-अभियुक्त-निचली अदालत द्वारा बरी-उच्च निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःगवाहों के साक्ष्य सुसंगत हैं और अप्रतिरोध्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं-गवाहों के बयानों में मामूली भिन्नताएं भौतिक नहीं हैं-रेज़ इप्सा लॉक्विटुर के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक गंभीर दुर्घटना थी जिससे कई मौतें हुईं-इसलिए दोषसिद्धि उचित है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 313-आयोजित की प्रकृति और उद्देश्यः धारा 313 के प्रावधान ये केवल औपचारिकता या उद्देश्यहीन नहीं हैं-इस प्रावधान का दोहरा उद्देश्य है कि पहला अभियुक्त के सामने अपराध साबित करने वाले साक्ष्य के पूरे भौतिक भागों को रखा जाए और दूसरा अभियुक्त को मामले के अपने पक्ष को समझाने का अवसर प्रदान किया जाए।

आपराधिक मुकदमा-विरोधाभासी बयान-साक्ष्य मूल्य-आयोजितःविरोधाभासों को सारगर्भित और सारगर्भित होना चाहिए ताकि अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके।

परीक्षण पहचान परेड-आयोजित करने की आवश्यकता-आयोजितःआवश्यकता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है-अदालत की पहचान कानून की नजर में अच्छी पहचान है-यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि इसे टीआई परेड से पहले किया जाना चाहिए।

लापरवाही-का निर्धारण-आयोजितःलापरवाही एक आत्यन्तिक लेकिन सापेक्ष शब्द नहीं है-लापरवाही के अस्तित्व का निर्धारण या क्या आचरण का तरीका लापरवाही के बराबर है, यह उपस्थित और आसपास के तथ्यों पर निर्भर करेगा-लापरवाही और अंशदायी लापरवाही के सवाल का निर्धारण करते समय, अदालत को 'उचित देखभाल' के मानदंड को अपनाना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ~धारा 133-इसके तहत नोटिस न देना-क्या यह अभियोजन पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। 279,337, 338 और भा.दं.सं. सी. 304 ए-आयोजितःतथ्यों पर, अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है जो उसकी सेवा न करने के कारण हुआ हो।

अपील-दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील-स्वामित्व के साथ हस्तक्षेप-आयोजितःआम तौर पर, अपील न्यायालय को दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए-लेकिन यह एक आत्यन्तिक नियम नहीं है-तथ्यों पर, उच्च निचली अदालत ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप किया क्योंकि वे कानून की त्रुटियों और साक्ष्य की सराहना से पीड़ित थे।

सिद्धांतः

उचित देखभाल का सिद्धांत-इसकी प्रयोज्यता।

रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत-दुर्घटना के लिए प्रयोज्यता मामले।

शब्द और वाक्यांशः

'जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना '-का अर्थ है।

'लापरवाही '-का अर्थ।

'दोषी लापरवाही 'और' दोषी लापरवाही '-

का अर्थ है।

अपीलार्थी-अभियुक्त यू/एस के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया था।279, 337, 338 और 304-ए भा.दं.सं. सी. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्लू2 ने पुलिस को बयान (Ex.P-2) दिया कि जब वह और उसका परिवार अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे, तो जिस जीप में उसके परिवार के सदस्य सवार थे और जो उसकी जीप से आगे जा रही थी, वह एक बस से टकरा गई जो बहुत तेज गति से आ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त को बस के चालक के रूप में नामित किया। उनके अनुसार आरोपी बस को खेतों में बड़े गड्ढों की ओर ले गया और पार्किंग करने के बाद बस भाग गई। घटना के चार चश्मदीद गवाह थे।

निचली अदालत ने अपने दिनांक 24.6.1999 के आदेश से आरोपी को दोषी ठहराया।लेकिन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड न आयोजित करने और डॉक्टर से पूछताछ न करने के मुद्दों पर विशेष न्यायाधीश द्वारा मामले को रिमांड पर लिए जाने के बाद, निचली निचली अदालत ने अपने दिनांक 11.6.2006 के आदेश से आरोपी को बरी कर

दिया।इसने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा और नोटिस की अनुपस्थिति में में यू/एस।133 मोटर वाहन अधिनियम, यह साबित नहीं किया जा सका कि आरोपी वास्तव में संबंधित समय पर बस चला रहा था।उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।;

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया; कि इसके लिए कोई सबूत नहीं था

अभियुक्त की पहचान करना या उसे अपराध करने वाले से जोड़ना; और यह कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने लापरवाही से बस चलाई थी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1.किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की जांच की जानी चाहिए।यह एक ऐसा तथ्य है जिसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है या अलगाव में देखा गया।परिचर परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए। एक व्यक्ति जो सड़क पर वाहन चलाता है, उसे इस कृत्य के साथ-साथ परिणाम के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वाहन की गति के संदर्भ में यह निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।ये दोनों कार्य एक असामान्य आचरण का अनुमान लगाते हैं।यहां तक कि जब कोई धीमी गति से लेकिन लापरवाही और लापरवाही से वाहन चला रहा हो, तो यह भा.दं.सं. सी. की खंड 279 के अर्थ के भीतर 'जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने' के बराबर होगा। यही कारण है कि विधायिका ने अपने विवेक में 'मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए इतना

जल्दबाजी या लापरवाही' शब्दों का उपयोग किया है। इस प्रकार, प्रारंभिक शर्तें यह हैं कि (ए) यह वह तरीका है जिसमें वाहन चलाया जाता है; (बी) इसे या तो जल्दबाजी में या लापरवाही से चलाया जाना चाहिए; और (सी) ऐसी लापरवाही या लापरवाही से गाड़ी चलाना ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जीवन को खतरा हो। एक बार जब ये तत्व संतुष्ट हो जाते हैं, तो भा.दं.सं. सी. की खंड 279 के तहत दंड लगाया जाता है। [पैरा 10] [248-ई-एच]

1.2.''लापरवाही' का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो मानव मामलों को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले विचारों द्वारा निर्देशित एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा या कुछ ऐसा करना जो समान विचारों द्वारा निर्देशित एक विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं करेगा।लापरवाही एक आत्यन्तिक शब्द नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष शब्द है; बल्कि यह एक तुलनात्मक शब्द है।किसी भी गणितीय रूप से सटीक सूत्र को सटीकता के साथ बताना मुश्किल है जिसके द्वारा किसी दिए गए मामले में लापरवाही या इसकी कमी को अचूक रूप से मापा जा सकता है।चाहे स्वयं लापरवाही हो या आचरण की प्रक्रिया लापरवाही के बराबर है, यह आम तौर पर उपस्थित और आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिन्हें न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना है।किसी दिए गए मामले में, वह न करना भी जो किसी को लापरवाही करना चाहिए था, गठित कर सकता है। [पैरा 11] [249-ए-सी]

1.3.न्यायालय को लापरवाही या अंशदायी लापरवाही के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए एक अन्य मापदंड, यानी 'उचित देखभाल' को अपनाना होगा।उचित देखभाल का सिद्धांत एक व्यक्ति (उदाहरण के लिए एक चालक) पर सड़क पर पैदल चलने वालों की देखभाल करने का दायित्व या कर्तव्य लगाता है और यह कर्तव्य तब उच्च स्तर पर पहुँचता है जब पैदल चलने वाले कम उम्र के बच्चे होते हैं।{पैरा 12] [249-डी]

1.4.ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा सहायता के लिए दबाव डाला जाने वाला दूसरा सिद्धांत रेस इप्सा लोकितुर का सिद्धांत है।यह सिद्धांत दो उद्देश्यों को पूरा करता है-एक यह कि एक दुर्घटना अपने स्वभाव से लापरवाही के कारण होने के साथ अधिक सुसंगत हो सकती है, जिसके लिए विरोधी पक्ष किसी अन्य कारण की तुलना में जिम्मेदार है और ऐसे मामले में, दुर्घटना का मात्र तथ्य इस तरह की लापरवाही का प्रथमदृष्टया प्रमाण है।दूसरा, यह उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए है जहां दावेदार दुर्घटना को साबित करने में समर्थ है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता है कि दुर्घटना कैसे हुई।अदालतों ने उन मामलों में भी रेज़ इप्सा लॉक्विटुर के सिद्धांत को लागू किया है जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।अधिनियम में स्वयं एक प्रावधान है जो भा.दं.सं. सी. में प्रावधान के समान खतरनाक रूप से गाड़ी चलाने के परिणामों से संबंधित है कि वाहन को सार्वजनिक जीवन के लिए खतरनाक तरीके से चलाया जाता है। जहाँ कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, उसे अधिनियम की खंड 184 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है। अदालतों ने 'दोषपूर्ण लापरवाही' और 'दोषपूर्ण लापरवाही' की अवधारणा को भी अपनाया है। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों पर विचार करना।'दोषी जल्दबाजी इस चेतना के साथ काम कर रही है कि शरारती और अवैध परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अक्सर इस विश्वास के साथ कि अभिनेता ने उनके होने को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है।अभेद्यता चेतना (/उक्सुरिया) के बावजूद कार्य करने से उत्पन्न होती है' 'निंदनीय लापरवाही' इस चेतना के बिना कार्य कर रही है कि अवैध और शरारती प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में जो दर्शाती हैं कि अभिनेता ने उन पर अनिवार्य सावधानी का प्रयोग नहीं किया है और अगर ऐसा होता, तो उन्हें होश होता। अभेद्यता सतर्कता के नागरिक कर्तव्य की उपेक्षा से उत्पन्न होती है।ऐसे मामले में, दुर्घटना का मात्र तथ्य इस तरह की लापरवाही का प्रथमदृष्टया प्रमाण है।इस उक्ति से

पता चलता है कि किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों पर रेस बोलता है और वाक्पटु है क्योंकि तथ्य अस्पष्ट हैं, जिसके परिणामस्वरूप तथ्यों से स्वाभाविक और उचित अनुमान, न कि एक अनुमानात्मक अनुमान, यह दर्शाता है कि यह कार्य किसी व्यक्ति के लापरवाहीपूर्ण आचरण के कारण है।[पैरा 13] [249-जी-एच 250-ए-ई]

'न्यायमूर्ति राजेश टंडन द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 पर एक विस्तृत टिप्पणी, प्रथम संस्करण, 2010-संदर्भित।

1.5.रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत दुर्घटना के मामलों पर समान रूप से लागू होता है न कि केवल नागरिक न्यायशास्त्र पर।इस प्रकार, इन सिद्धांतों को समान रूप से आपराधिक मामलों तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते परिचर परिस्थितियाँ और बुनियादी तथ्य साबित हों।या तो दुर्घटना को उचित और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए या इस सिद्धांत को लागू करने से पहले यह एक स्वीकृत तथ्य होना चाहिए।यह सिद्धांत बाद के चरण में सहायता के लिए आता है जहां यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना कैसे और किसकी लापरवाही के कारण हुई।दुर्घटना का तथ्य स्थापित हो जाने के बाद, न्यायालय उचित साक्ष्य की सहायता से परिचर परिस्थितियों की सहायता ले सकता है और रेज़ इप्सा लोकितुर के सिद्धांत को लागू कर सकता है।दुर्घटना की घटना के मात्र तथ्य का मतलब यह नहीं है कि यह किसी की लापरवाही के कारण होना चाहिए।ऐसे मामलों में जहां लापरवाही प्राथमिक कारण है, यह हमेशा नहीं हो सकता है कि इसे साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हो।ऐसे मामलों में लापरवाही साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं।परिवेशीय साक्ष्य में ऐसे तथ्य होते हैं जो आवश्यक रूप से लापरवाही को एक स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करने के बजाय एक तार्किक निष्कर्ष के रूप में इंगित करते हैं।इस सिद्धांत के तत्वों को इस प्रकार कहा जा

सकता हैः(1) यह घटना किसी की लापरवाही के कारण नहीं हुई होगी।(2) अभिलेख पर साक्ष्य इस संभावना को खारिज करता है कि पीड़ित या किसी तीसरे पक्ष की कार्रवाई घटना के पीछे का कारण हो सकती है और (3) अभियुक्त लापरवाही कर रहा था और पीड़ित की देखभाल का कर्तव्य था।[पैरा 18] [255-ए-एफ]

मोहम्मद.अयनुद्दीन उपनाम मियाम बनाम राज्य एपी (2000) 7 एससीसी 72:2000(2) पूरक एससीआर 15; ठाकुर 9. बनाम पंजाब राज्य (2003) 9 एससीसी 208-पर भरोसा किया गया।

एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 648; नरेश गिरि बनाम एम. पी. राज्य (2008) 1 एस. सी. सी. 791:2007 (11) एस. सी. आर. 987-संदर्भित।

2.1.यह नहीं कहा जा सकता है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं और साइट योजना प्रदर्शनी पी29/पी3 अपीलकर्ता की ओर से कोई लापरवाही नहीं दिखाती है।विचाराधीन बस निश्चित रूप से दुर्घटना में शामिल थी, वास्तव में, इस बात पर कोई गंभीर विवाद नहीं है कि जीप और बस के बीच दुर्घटना घटना स्थल पर हुई थी।रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक गंभीर दुर्घटना थी जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।दुर्घटना के बाद बस चालक ने बस को दूसरी जगह ले जाया। [पैरा 27] [259 -बी-ई]

2.2.गवाहों के बयान में एकरूपता है कि आरोपी वाहन चला रहा था और घटना स्थल से दूर एक स्थान पर वाहन खड़ा करने के बाद वह भाग गया था।इन गवाहों के बयान जो पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्शनी पी 2 द्वारा समर्थित हैं, जिनके लिए

पीडब्लू 11 की प्रतिपरीक्षा के दौरान शायद ही कोई चुनौती थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कोई गंभीर या भौतिक विरोधाभास नहीं है, पीडब्लू 2 के परचा बयान, प्रदर्शनी पी 2 में बहुत कम है। जब घटना की तारीख से काफी समय बीत जाने के बाद गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं तो उनके बयानों में मामूली बदलाव होना तय है।अदालत इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि ये गवाह बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं।गवाहों की सच्चाई इस तथ्य से भी प्रदर्शित होती है कि पीडब्लू1 ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कहा कि वह बेहोश थी और उसने चालक को नहीं देखा था।इस प्रकार, तीन गवाहों, यानी पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने दुर्घटना का सही विवरण दिया है। उनके बयान विश्वास के योग्य हैं और अदालत के लिए इन गवाहों पर अविश्वास करने का कोई अवसर नहीं है। [पैरा 28] [259-जी-एच; 260-ए-सी]

2.3.यह एक तय सिद्धांत है कि गवाहों के बयानों में भिन्नताएं जो न तो सामग्री हैं और न ही अभियोजन के मामले को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं।

प्रतिकूल रूप से, अदालतों द्वारा नजरअंदाज किया जाना चाहिए।[पैरा 28] [260 -

डी)

राज्य बनाम सरवनन और अन्र (2008) 17 एससीसी 587:2008 (14) एस. सी. आर. 405; सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 13 एस. सी. सी. 657:2010 (15) एससीआर 452 -पर भरोसा किया।

2.4.यह भी एक तय सिद्धांत है कि गवाहों के बयानों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अदालत को पूरे बयान से अलग एक सजा नहीं लेनी चाहिए और इसके उचित संदर्भ को नजरअंदाज करते हुए, एक पक्ष के खिलाफ या पक्ष में इसका उपयोग करना चाहिए।विरोधाभासों को सारवान और सारवान होना चाहिए ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।[पैरा 28] [260-ई-एफ]

आत्माराम बनाम मध्य प्रदेश अन्य का राज्य (2012) 5 एस. सी. सी. 738- संदर्भित।

2.5.वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले गवाहों या पास में चलाए जा रहे वाहन में यात्रा कर रहे लोगों के बयानों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वाहन में सवार लोग उसी दिशा में देख रहे हों। हो सकता है कि यह केवल शोर या दुर्घटना के परिणामस्वरूप वास्तविक प्रभाव के कारण होने वाली गड़बड़ी से आकर्षित हुआ हो।[पैरा 29] [260-जी-एच; 261-ए]

2.6. दो कारणों से परीक्षण पहचान (अपीलकर्ता की परेड) आयोजित करना आवश्यक नहीं था।सबसे पहले, अपीलकर्ता पहले से ही राहगीरों के लिए ज्ञात था जिनके पास था बस चलाते समय उसे पहचाना और उसका नाम बताया और दूसरी बात, वह विधिवत देखा गया, हालांकि एक छोटी लेकिन उचित अवधि के लिए, जब बस खड़ी करने के बाद, वह बस से उतरकर भाग गया।[पैरा 33] [264-जी-एच; 265-ए]

2.7. वर्तमान मामले में आरोपी को पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने देखा था।इन गवाहों ने अदालत में अभियुक्तों की पहचान भी की।यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि अदालत में उसकी पहचान होने से पहले उसे गवाहों को दिखाया गया था। अदालत की पहचान अपने आप में कानून की नजर में एक अच्छी पहचान है। हमेशा ऐसा नहीं होता यह आवश्यक है कि यह परीक्षण पहचान परेड से पहले होना चाहिए। यह हमेशा किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।एक मामले में, परीक्षण पहचान परेड आयोजित करना भी आवश्यक नहीं हो सकता है, जबकि दूसरे में, ऐसा करना

आवश्यक हो सकता है।इस प्रकार, इस संबंध में कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं कहा जा सकता है।[पैरा 32] [262-जी-एच; 263-ए]

नागेश्वर श्री कृष्ण घोबे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 4 एससीसी 23:1973 (2) एससीआर 377; मायलादिम्मल सुरेंद्रन और अन्य. वी.केरल राज्य (2010) 11 एस. सी. सी. 129:2010 (10)

एससीआर 916; श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2012 (6) स्केल 381- पर भरोसा किया गया।

मुल्ला और अन्र. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एससीसी 508:2010 (2) एस. सी. आर. 633; अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 107- संदर्भित।

3.1.उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि न्यायालय को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी ने वाहन के मालिक को मोटर वाहन अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस नहीं दिया था।याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वाहन के चालक की पहचान घटना स्थल पर की गई थी और यहां तक कि राहगीरों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सूचित किया था कि चालक-आरोपी वाहन का मालिक था।प्राथमिकी आर. में ही अभियुक्त का नाम विधिवत दर्ज किया गया था।यह तथ्य निर्विवाद बना रहा।यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी वाहन नहीं चला रहा था, हालांकि यह विवादित नहीं था कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक है।यदि ऐसा है, तो जब निचली अदालत द्वारा Cr.P.C की खंड 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था, तो इनकार के अलावा, उसने आगे कुछ नहीं कहा। अभियुक्त को सबसे अच्छी तरह

से ज्ञात कारणों के लिए, यह बताने के बजाय कि उसने उस तारीख को अपना वाहन चलाने के लिए किसे दिया था, उसने चुप रहना पसंद किया और अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार कर दिया।[पैरा 34] [265-बी-डी]

3.2.यह सच है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है, लेकिन खंड 313 के प्रावधान केवल औपचारिकता या उद्देश्यहीन नहीं हैं।उनका दोहरा उद्देश्य है, पहला, कि दोषारोपण करने वाले साक्ष्य के पूरे भौतिक भागों को कानून के अनुसार अभियुक्त के सामने रखा जाना चाहिए और दूसरा, अभियुक्त को अपने आचरण या मामले के अपने संस्करण को समझाने का अवसर प्रदान करना।अभियुक्त को यह अवसर प्रदान करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है। यदि अभियुक्त जानबूझकर इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो कानूनी परिणामों का पालन करना होगा, विशेष रूप से जब आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम में अभियुक्त से कुछ तथ्यों का खुलासा करने की उम्मीद की जाएगी जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी में हो सकते हैं और जिनका मामले पर असर हो सकता है।[पैरा 35]

[265-ई-जी]

3.3.अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस न देने से अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और किसी भी मामले में अभियुक्त इसका कोई लाभ नहीं ले सकता है।[पैरा 36] [265-एच; 266-ए]

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील न्यायालय आम तौर पर दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा, लेकिन यह एक आत्यन्तिक नियम नहीं है।वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के लिए त्रयी अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति जाने के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण थे।यह साक्ष्य की अनुपलब्धता या सामग्री की उपस्थिति और अभियोजन पक्ष के मामले के

लिए घातक साबित होने वाले गंभीर विरोधाभासों का मामला नहीं था।पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा दिए गए नेत्र विवरण पर विश्वास न करने के लिए निचली निचली अदालत के समक्ष कोई प्रशंसनीय कारण नहीं था और निचली अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि आरोपी की घटना के स्थान पर और यहां तक कि निचली अदालत में भी विधिवत पहचान की गई थी।निचली निचली अदालत निश्चित रूप से कानून की त्रुटि और साक्ष्य की सराहना में गिर गई है।एक बार जब निचली निचली अदालत ने साक्ष्य के भौतिक टुकड़े को नजरअंदाज कर दिया है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अपने सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रही है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो यह न्यायाधीश की विफलता होगी।कुछ मामलों में, साक्ष्य के मूल्यांकन में ऐसी त्रुटि विकृत निष्कर्षों को दर्ज करने के बराबर भी हो सकती है।निचली निचली अदालत ने पहली बार 24 जून, 1999 को अपराधों के अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया था।हालाँकि, अपील पर, मामले को दो आधारों पर रिमांड पर लिया गया था, अर्थात, परीक्षण पहचान परेड का आयोजन न करने और डॉक्टर की जांच न करने के प्रभाव पर विचार करते हुए।रिमांड पर आने पर निचली निचली अदालत ने पहले की तुलना में अलग दृष्टिकोण अपनाया था और 11 मई, 2006 के फैसले में उसने आरोपी को बरी कर दिया था।यह स्वयं निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति जाने के फैसले में उच्च निचली अदालत द्वारा हस्तक्षेप का आधार बन गया।ट्रायल निचली अदालत के फैसले से, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के आयोजन या डॉक्टर की जांच न होने के प्रभाव पर कोई ठोस चर्चा नहीं होती है।इसके विपरीत, निचली निचली अदालत ने कुछ धारणाओं पर अपना फैसला सुनाया।गवाहों में से किसी ने भी, यहां तक कि आरोपी ने भी अपने बयान में नहीं कहा था कि जीप तेज गति से चल रही थी, लेकिन फिर भी निचली निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि जीप तेज गति से चल रही थी

और उसे ठीक से नहीं चलाया जा रहा था।निचली निचली अदालत ने यह भी दर्ज किया कि इस बात का संदेह पैदा होता है कि दुर्घटना के समय आरोपी वास्तव में बस चला रहा था या नहीं और पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी।निचली निचली अदालत चश्मदीद गवाहों के बयान को नजरअंदाज कर सकती थी, विशेष रूप से जब वे भरोसेमंद, भरोसेमंद थे और दुर्घटना का सबसे उपयुक्त नेत्र विवरण देते थे।इसलिए, निचली निचली अदालत के फैसले में कानून की त्रुटियां और साक्ष्य दोनों की सराहना की गई।निचली अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने के फैसले में उच्च निचली अदालत का हस्तक्षेप किसी भी अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।[अनुच्छेद 37,38 और 39] [266-बी; 269-ई-एच; 270-ए-जी]

यू. पी. राज्य बनाम बैन्ने और एनर। (2009) 4 एस. सी. सी. 271; स्फेट ऑफ हरियाणा अन्य शकुंतला और अन्य। 2012 (4) स्केल 526-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भः

(2012) 2 एस. सी. सी. 648 पैरा 15 में संदर्भित

2007 (11) एस. सी. आर. 987 पैरा 16 में संदर्भित

2000 (2) पूरक।एस. सी. आर. 15 पैरा 17 पर सेवानिवृत्त हुआ

(2003) 9 एस. सी. सी. 208 पैरा 19 पर आधारित है

2008 (14) एस. सी. आर. 405 पैरा 28 पर आधारित है।

2010 (15) एस. सी. आर. 452 पैरा 28 पर आधारित है।

(2012) 5 एस. सी. सी. 738 पैरा 28 में संदर्भित

1973 (2) एस. सी. आर. 377 पैरा 29 पर आधारित है।

2010 (2) एस. सी. आर. 633 पैरा 30 को संदर्भित

(2012) 4 एस. सी. सी. 107 पैरा 30 में संदर्भित

2010 (10) एस. सी. आर. 916। पैरा 31 पर आधारित

2012 (6) स्केल 381 पैरा 32 पर आधारित है

(2009) 4 एस. सी. सी. 271 पैरा 37 पर निर्भर

2012 (4) स्केल 526 पैरा 37 पर आधारित है

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः2009 की दाण्डिक अपीलीय सं 1838।

एस. बी. सी. आर. एल. में जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.8.2008 के निर्णय और आदेश से। अपील सं. 589

2007 से।

पी. एस. पटवालिया, शंकर अपीलकर्ता के लिए विभाजन करते हैं।

सूर्यनारायण सिंह, प्रगति नीखर उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय स्वतंत्र कुमार, जे.

1. वर्तमान अपील 12 अगस्त, 2008 को जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः

पीडब्लू2 के एक व्यक्ति, सुखदेव सिंह ने 20 अप्रैल, 1991 को एम. आई. ए. अलवर पुलिस थाने में पुलिस को सूचना दी थी और कहा था कि उसी दिन सुबह लगभग 9.15 पूर्वाह्न वह अपने बहनोई, जोगा सिंह की शादी में शामिल होने के लिए जीप से अलवर से गोविंदगढ़ जा रहा था।जब वे बग्गड़ तिराया पहुँचे, तो एक जीप नं.

आर. एन. ए.-638 भी उनकी जीप से आगे जा रहा था और उक्त जीप में उनकी पत्नी चेत कौर, बेटी रिंकी, ससुर, लाहौरी सिंह, सास, गीता और चाचा ससुर (फुफी सासूर) निरंजन सिंह और उनकी पत्नी कैलाशवती और उनके बहनोई मुल्तान सिंह और उनके बेटे टिंकू यात्रा कर रहे थे।उनके आगे एक मारुति कार भी जा रही थी।बस नं. आर. एन. ए. 339 बागगढ़ तिराया की ओर से बहुत तेज गति से आ रहा था।मारुति कार के चालक ने तुरंत खुद को बचाने के लिए अपनी कार को एक तरफ मोड़ दिया और बस नंबर वाली जीप से टकरा गई। आरएनए-638।इस घातक दुर्घटना में चेत कौर, रिंकी, गीता और जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई।जीप में सवार अन्य लोगों, विशेष रूप से लाहौरी सिंह, निरंजन सिंह, कैलाशवंती और टिंकू की हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बाद में उनकी मौत हो गई।इस प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, रवि कपूर बस चला रहा था जो बस को खेतों में बड़े गड्ढों की ओर ले गया और वहां बस खड़ी करने के बाद वह मौके से भाग गया।

3. आई. डी. 1 के आधार पर, आरोपी रवि कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की खंड 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जाँच अधिकारी, पीडब्लू11 ने जाँच की, स्थल योजना, Ex.P3 तैयार की, और विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए।अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की खंड 279,337,338 और 304-ए के तहत आरोप पत्र (दंड प्रक्रिया भा.दं.सं., 1973 की खंड 173 के तहत रिपोर्ट) दायर किया गया था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए और उस पर मुकदमा चलाया गया।

4. अभियोजन पक्ष ने चार चश्मदीद गवाहों, डॉक्टरों और स्वयं जांच अधिकारी सहित 11 गवाहों से पूछताछ की।अभियोजन पक्ष के मामले को बंद करने पर, आरोपी के खिलाफ सभी दोषपूर्ण साक्ष्य उसके सामने रखे गए और आईडी1 की खंड 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने पूर्ण इनकार का रुख अपनाया और

कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला झूठा था।निचली निचली अदालत ने 11 मई, 2006 के अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में समर्थ नहीं है और आरोपी दोषमुक्ति के आदेश का हकदार है।नतीजतन, अदालत ने आरोपी रवि कपूर को उपरोक्त सभी आरोपों से बरी कर दिया।इस स्तर पर ही, हम निचली निचली अदालत के फैसले के प्रासंगिक उद्धरण का उल्लेख कर सकते हैं, जो आरोपी को बरी करने का कारण हैः

"तत्काल मामले में अब केवल 3 गवाहों पर विचार किया जाना बाकी है।, पी. डब्ल्यू. 2-सुखदेव सिंह; P.W.4-Multan सिंह और P.W.11-Sohan लाल जो जाँच अधिकारी हैं।अदालत को इन गवाहों द्वारा दी गई गवाही पर विचार करना होगा और यह देखना होगा कि क्या इन गवाहों के बयानों से यह साबित होता है कि आरोपी बस को लापरवाही से चला रहा था और जीप को टक्कर मार रहा था या नहीं और क्या आरोपी रवि कपूर उक्त बस नंबर 1 चला रहा था।आर. एन. ए. 339 दुर्घटना के समय या नहीं? इस संबंध में, P.W.2-Sukhdev सिंह, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति भी हैं, ने अपने परचे बयान Ex.P2 (sic) में कहा है कि एक मारुति वैन जीप से आगे चली गई थी जो दुर्घटना का शिकार हो गई थी और दुर्घटना में शामिल उक्त जीप के पीछे उनकी जीप थी।ये तीनों वाहन सड़क के एक तरफ थे और एक दूसरे से 20 फीट की दूरी पर थे।एक बस आई नं। आर. एन. ए.-339 बागर तिराहा के पास उनकी ओर आया और इस बस को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया और सीधे जीप से टकरा गई।हालांकि, मारुति कार जो दुर्घटना जीप से आगे थी और जीप जिसमें वह यात्रा कर रहे थे और जो दुर्घटना जीप के पीछे थी, उक्त दुर्घटना में बस से बच गई।ये दोनों वाहन सड़क के कच्छ की ओर मुड़ गए।इस गवाह ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बस का चालक नं.आर. एन. ए.-339 ने दुर्घटनाग्रस्त जीप में यात्रा कर रहे व्यक्तियों को मारने के इरादे से जीप को टक्कर मार दी।उन्होंने आगे कहा

है कि उन्होंने बस के चालक की पहचान की और उन पर रवि कपूर को आरोपित किया गया था। राहगीरों ने भी उसकी पहचान की और उसने उसके नाम का भी खुलासा किया।इसलिए, अब इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या इस गवाह द्वारा अपने परचे बयान-प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट किए गए तथ्य पूरी तरह से साबित होते हैं या नहीं?इस गवाह के मुख्य परीक्षण के अवलोकन से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि इस गवाह ने अदालत के समक्ष बयान में कहा है कि मारुति कार सबसे आगे थी और जिस जीप में वह बैठा था, वह मारुति कार के पीछे थी और जिस जीप से दुर्घटना हुई, वह उपरोक्त वाहनों के पीछे थी।इसलिए, इन परिस्थितियों में इस गवाह के अपने परचे बयान में और अदालत में इस तथ्य के संबंध में दिए गए बयानों में विरोधाभास है कि क्या दुर्घटनाग्रस्त जीप उपरोक्त वाहनों के आगे या पीछे थी।अदालत में अपने बयान में वह कहता है कि जिस जीप में वह बैठा था, वह दुर्घटनाग्रस्त जीप के पीछे थी और वह खुद चालक की सीट के पीछे बैठा था। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में यह सुरक्षित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस गवाह ने वास्तव में दुर्घटना को देखा है।क्योंकि इस तथ्य के बारे में भौतिक आत्म-विरोधाभास हैं कि क्या इस गवाह की जीप दुर्घटनाग्रस्त जीप के आगे थी या पीछे।...

इन परिस्थितियों में इस गवाह के बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बस का चालक लापरवाही कर रहा था, बस की गति क्या थी और दुर्घटनाग्रस्त जीप सड़क के दाहिने तरफ थी।इस गवाह का यह भी कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त जीप के आगे एक जीप और एक मारुति कार थी, लेकिन इन दोनों वाहनों के चालकों ने अपने वाहनों को बस से बचा लिया और इसलिए बस ने उस जीप को टक्कर मार दी जिसमें यह गवाह बैठा था।अदालत को यह देखना होगा कि अगर बस का चालक वास्तव में लापरवाही से बस चला रहा था, तो वह दुर्घटनाग्रस्त जीप से आगे जा रही जीप और मारुति कार से क्यों नहीं टकराया और वह दुर्घटनाग्रस्त जीप से क्यों टकरा गया।अदालत को इस बात

पर भी विचार करना है कि क्या दुर्घटना जीप के चालक द्वारा जीप को ओवरटेक करने के कारण हुई थी। क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होने वाले गवाहों ने कहा है कि बस के दाईं ओर मोच का सामना करना पड़ा।लेकिन अभियोजन पक्ष ने कोई यांत्रिक विशेषज्ञ रिपोर्ट दायर नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई विशेषज्ञ गवाह पेश किया है जो यह साबित कर सकता है कि बस ने वास्तव में जीप को सामने से टक्कर मार दी थी।यह भी स्पष्ट नहीं है कि आगे की बस को कोई नुकसान हुआ है या नहीं।लाल/जाँच अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान के अवलोकन से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि दुर्घटना उस स्थान पर हुई थी जहाँ सड़क पर मोड़/क्रॉसिंग थी और इसलिए बस के चालकों के साथ-साथ जीप दोनों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए था।इसके अलावा इस गवाह के बयान से यह भी स्पष्ट नहीं है कि बस वास्तव में जीप के सामने वाले हिस्से से टकरा गई थी।उन्होंने कहा है कि दुर्घटना बीच के वाहन के ओवरटेकिंग के कारण हो सकती है।जबकि इस गवाह को यह साबित करना चाहिए था कि दुर्घटना बस और जीप के बीच आमने-सामने की टक्कर थी।इसके अलावा, इस गवाह ने आरोपी की पहचान की कार्यवाही नहीं की क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बताया था कि रवि कपूर आरोपी है और वह बस का मालिक और चालक है।इस गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने वाहन के मालिक को एम. वी. अधिनियम की खंड 133 के तहत कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा। इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस गवाह के बयानों से यह स्पष्ट है कि न तो बस के मालिक को M.V.Act की खंड 133 के तहत नोटिस दिया गया था और न ही आरोपी की पहचान की कार्यवाही की गई थी।हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि रवि कपूर बस का चालक था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया और उससे पूछताछ नहीं की, जो यह समझा सकता था कि रवि कपूर बस नं. आरएनए-339।वास्तव में अभियोजन पक्ष को

चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने चाहिए थे और उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए था जो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि दुर्घटना के समय रवि कपूर बस चला रहा था और अभियुक्तों की पहचान की कार्यवाही भी बहुत आवश्यक थी क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दोनों गवाहों ने आरोपी रवि कपूर की पहचान नहीं की है या यह कि दुर्घटना रवि कपूर द्वारा बस के चालक की लापरवाही और लापरवाही के कारण हुई थी।गवाहों में से एक ने कहा है कि उसने चालक को मौके से भागते देखा था, लेकिन उसने यह नहीं कहा है कि उसने बस के चालक को जीप से टकराते देखा था। एम. वी. अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस बहुत आवश्यक था जो यह साबित कर सकता था कि रवि कपूर वास्तव में बस नं.दुर्घटना के समय आरएनए-339।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि बस को लापरवाही से चलाया जा रहा था"

5. निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को उच्च निचली अदालत द्वारा उलट दिया गया, जिसने दोषमुक्ति के फैसले को दरकिनार कर दिया।साक्ष्य की सराहना करने पर, उच्च निचली अदालत ने 12 अगस्त, 2008 के अपने फैसले के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत का फैसला गलत था और विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की खंड 133 के तहत नोटिस देने के मुद्दे पर विचार करते हुए, अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

"अब जहां तक मोटर वाहन अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस का संबंध है, जो मालिक को नहीं दिया गया था, क्योंकि पीडब्लू 2 सुख देव सिंह, मुलतान सिंह पी. डब्ल्यू. 4 के बयान में कहा गया है कि आरोपी प्रतिवादी चालक था और उन्होंने मौके पर और साथ ही अदालत में भी उसकी पहचान की है।ऐसी स्थिति में, मोटर वाहन की खंड 133 के तहत मालिक को नोटिस देने की कोई प्रासंगिकता नहीं है।इस प्रकार, पीडब्लू 2 सुख देव सिंह और पीडब्लू 4 मुल्तान सिंह के बयान के आलोक में

किसी पहचान परेड की आवश्यकता नहीं है।प्राथमिकी आर. Ex.P.1 से पता चलता है कि

6. उच्च न्यायालय ने आरोपी को भा.दं.सं. सी. की खंड 304-ए के तहत दोषी ठहराया और उसे दो साल के लिए साधारण कारावास और Rs.5000 के जुर्माने के साथ छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।अदालत ने आरोपी को भा.दं.सं. सी. की धारा 279 और 337 के तहत अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया, जिसमें उसे Rs.1000 के जुर्माने के साथ छह महीने का साधारण कारावास, जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने का साधारण कारावास और Rs.500 के जुर्माने के साथ एक महीने का साधारण कारावास, जुर्माने का भुगतान न करने पर क्रमशः 15 दिनों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित, वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

7. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए अनुरोध किया है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति जाने के फैसले को बहाल किया जाए और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाए।विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:(क) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अपील न्यायालय को आम तौर पर दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह विकृत और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत न हो।दोषमुक्ति जाने के आदेश के खिलाफ अपील का दायरा बहुत सीमित है और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति जाने के फैसले को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।(ख) अभियुक्त की पहचान करने या उसे अपराध करने से जोड़ने के लिए अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है, अर्थात, वह उक्त वाहन चला रहा था या नहीं।वास्तव में, वकील के अनुसार, यह दिखाने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि आरोपी रवि कपूर दुर्घटना में शामिल बस चला रहा था।(ग) भले ही यह माना जाता है कि आरोपी संबंधित समय पर बस चला रहा

था, फिर भी यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने लापरवाही से बस चलाई थी।इन दोनों मामलों में किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में में, अपीलकर्ता दोषमुक्ति का हकदार है।

8. उपर्युक्त दलीलों का खंडन करते हुए, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना के चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने पूरी घटना को स्पष्ट रूप से बताया है।विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा 28 अक्टूबर, 1999 के आदेश द्वारा परीक्षण पहचान परेड को न रोकने और डॉक्टर की बिना जांच के मुद्दे के संबंध में मामले को रिमांड पर लिए जाने के बाद, निचली अदालत ने 11 मई, 2006 के अपने उपर्युक्त फैसले के माध्यम से 24 जून, 1999 के अपने पहले के फैसले को बाधित कर दिया था।निचली अदालत के इस बाद के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के फैसले को दोषसिद्धि के फैसले में बदल दिया। यह स्वयं दर्शाता है कि निचली अदालत के बाद के निर्णय में स्पष्ट त्रुटियाँ थीं और साक्ष्य के उचित मूल्यांकन का पूर्ण अभाव था।इसलिए, इस न्यायालय द्वारा उस निर्णय को बहाल नहीं किया जाना चाहिए।उनके अनुसार, पीडब्लू2, पीडब्लू4 और पीडब्लू11 के बयान स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले को स्थापित करते हैं। गवाहों के बयानों और परचा बयान आदि के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. सबसे पहले, हम अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए अंतिम विवाद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना से संबंधित है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित निर्णय दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ उलट निर्णय है।

10. अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए वाद (ख) और (ग) की योग्यता या अन्यथा की जांच आदेशने के लिए, न्यायालय के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह जांच आदेशना आवश्यक है कि (क) जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना क्या है; और (ख) क्या इसे परिचर परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है।किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की जांच की जानी चाहिए।यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अलग से समझने या देखने में असमर्थ है।परिचर परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए।एक व्यक्ति जो सड़क पर वाहन चलाता है, उसे इस कृत्य के साथ-साथ परिणाम के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।वाहन की गति के संदर्भ में यह निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।ये दोनों कार्य एक असामान्य आचरण का अनुमान लगाते हैं।यहां तक कि जब कोई धीमी गति से लेकिन लापरवाही और लापरवाही से वाहन चला रहा हो, तो यह भा.दं.सं. सी. की खंड 279 के अर्थ के भीतर 'जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने' के बराबर होगा। यही कारण है कि विधायिका ने अपने विवेक में 'मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए इतना जल्दबाजी या लापरवाही' शब्दों का उपयोग किया है।इस प्रकार, प्रारंभिक शर्तें यह हैं कि (ए) यह वह तरीका है जिसमें वाहन चलाया जाता है; (बी) इसे या तो जल्दबाजी में या लापरवाही से चलाया जाना चाहिए; और (सी) ऐसी लापरवाही या लापरवाही से गाड़ी चलाना ऐसा होना चाहिए जिससे मानव जीवन को खतरा हो।एक बार जब ये तत्व संतुष्ट हो जाते हैं, तो भा.दं.सं. सी. की खंड 279 के तहत दंड लगाया जाता है।

11. ''लापरवाही' का अर्थ है कुछ ऐसा करना जो मानव मामलों को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले विचारों द्वारा निर्देशित एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति करेगा या कुछ ऐसा करना जो समान विचारों द्वारा निर्देशित एक विवेकपूर्ण और विवेकपूर्ण

व्यक्ति नहीं करेगा।लापरवाही एक आत्यन्तिक शब्द नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष शब्द है; बल्कि यह एक तुलनात्मक शब्द है।किसी भी गणितीय रूप से सटीक सूत्र को सटीकता के साथ बताना मुश्किल है जिसके द्वारा किसी दिए गए मामले में लापरवाही या इसकी कमी को अचूक रूप से मापा जा सकता है।चाहे स्वयं लापरवाही हो या आचरण की प्रक्रिया लापरवाही के बराबर है, यह आम तौर पर उपस्थित और आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिन्हें न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना है।किसी मामले में, वह न करना भी जो किसी को करना चाहिए, लापरवाही हो सकती है।

12. न्यायालय को लापरवाही या अंशदायी लापरवाही के प्रश्न का निर्धारण करने में एक अन्य मापदंड, अर्थात 'उचित देखभाल' को अपनाना होगा।उचित देखभाल का सिद्धांत एक व्यक्ति (उदाहरण के लिए एक चालक) पर सड़क पर पैदल चलने वालों की देखभाल करने का दायित्व या कर्तव्य लगाता है और यह कर्तव्य तब उच्च स्तर तक पहुँचता है जब पैदल चलने वाले कम उम्र के बच्चे होते हैं।यह कहना स्वयंसिद्ध है कि सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाते समय, चालकों पर यह देखना एक अंतर्निहित कर्तव्य है कि उनके वाहन चलाने से सड़क के सही उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरा न हो, वे वाहन उपयोगकर्ता या पैदल चलने वाले हो सकते हैं।उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरों के लिए खतरे से बचने के लिए पर्याप्त देखभाल करें।

13. ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा सहायता के लिए दबाव डाला जाने वाला दूसरा सिद्धांत रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत है।यह सिद्धांत दो उद्देश्यों को पूरा करता है-एक यह कि एक दुर्घटना अपने स्वभाव से लापरवाही के कारण होने के साथ अधिक सुसंगत हो सकती है, जिसके लिए विरोधी पक्ष किसी अन्य कारण की तुलना में जिम्मेदार है और ऐसे मामले में, दुर्घटना का मात्र तथ्य इस तरह की लापरवाही का प्रथमदृष्टया प्रमाण है।दूसरा, यह उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए है जहां दावेदार दुर्घटना को साबित करने में समर्थ है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता है कि दुर्घटना कैसे

हुई। अदालतों ने उन मामलों में भी रेज़ इप्सा लॉक्विटुर के सिद्धांत को लागू किया है जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। अधिनियम में स्वयं एक प्रावधान है जो भा.दं.सं. सी. में प्रावधान के समान खतरनाक रूप से गाड़ी चलाने के परिणामों से संबंधित है कि वाहन को सार्वजनिक जीवन के लिए खतरनाक तरीके से चलाया जाता है।जहाँ कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, उसे अधिनियम की खंड 184 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है। अदालतों ने सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 'दोषपूर्ण लापरवाही' और 'दोषपूर्ण लापरवाही' की अवधारणा को भी ध्यान में रखा है।'दोषी जल्दबाजी इस चेतना के साथ काम कर रही है कि शरारती और अवैध परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अक्सर इस विश्वास के साथ कि अभिनेता ने उनके होने को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है। अचेतनता चेतना (विलासिता) के बावजूद कार्य करने से उत्पन्न होती है।''निंदनीय लापरवाही' इस चेतना के बिना कार्य कर रही है कि अवैध और शरारती प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में जो दर्शाती हैं कि अभिनेता ने उन पर अनिवार्य सावधानी का प्रयोग नहीं किया है और अगर ऐसा होता, तो उन्हें होश होता। अभेद्यता सतर्कता के नागरिक कर्तव्य की उपेक्षा से उत्पन्न होती है। ऐसे मामले में दुर्घटना का मात्र तथ्य इस तरह की लापरवाही का प्रथमदृष्टया प्रमाण है। इस उक्ति से पता चलता है कि किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों पर रेस बोलता है और वाक्पटु है क्योंकि तथ्य अस्पष्ट हैं, जिसके परिणामस्वरूप तथ्यों से स्वाभाविक और उचित अनुमान, न कि एक अनुमानात्मक अनुमान, यह दर्शाता है कि यह कार्य किसी व्यक्ति के लापरवाहीपूर्ण आचरण के कारण है।[रेफ. न्यायाधीश राजेश टंडन की 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988 पर एक विस्तृत टिप्पणी' (पहला संस्करण, 2010)।

14. हमने इन सिद्धांतों पर ध्यान दिया है ताकि वर्तमान मामले में उठाए गए प्रश्नों की उनके सही परिप्रेक्ष्य में आदेश की जा सके।हम देख सकते हैं कि आकस्मिक

नागरिक या यातनापूर्ण न्यायशास्त्र के दायरे में आने वाले कुछ सिद्धांत वर्तमान की तरह आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत आने वाले मामलों पर काफी लागू होते हैं।

15. अब, हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जो ऐसे प्रश्नों के निर्णायक उत्तर देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2012) 2 एस. सी. सी. 648] के मामले में जहां एक वाहन का चालक नशे की हालत में देर रात को तेज गति से वाहन चला रहा था और फुटपाथ पर सो रहे सात मजदूरों की मौत हो गई, अन्य आठ घायल हो गए, इस अदालत ने अपील को खारिज करते हुए, 'ज्ञान' के आधार पर आपराधिक दोष निर्धारित करने के लिए परीक्षणों को निम्नानुसार निर्धारित कियाः

"41. खतरनाक चरित्र और अधिनियम के संभावित प्रभाव की जानकारी के साथ सार्वजनिक सड़क पर जल्दबाजी या लापरवाही से गाड़ी चलाना और जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है, गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में आ सकती है। जल्दबाजी या लापरवाही से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, यदि किसी जोखिम के बारे में जानता है कि किसी विशेष परिणाम की संभावना है और वह परिणाम होता है, तो उसे न केवल कार्य के लिए बल्कि परिणाम के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है।कानून के मामले के रूप में-भा.दं.सं. सी. के प्रावधानों को देखते हुए-वे मामले जो खंड 299 के अंतिम खंड के भीतर आते हैं, लेकिन खंड 300 के खंड "चौथा" के भीतर नहीं आते हैं, वे लापरवाही या लापरवाही के मामलों को शामिल कर सकते हैं जो इसके खतरनाक परिणामों की संभावना के ज्ञान के साथ किए गए हैं और भा.दं.सं. सी. की खंड 304 भाग II के तहत सजा हो सकती है। भा.दं.सं. सी. की खंड 304-ए किसी भी व्यक्ति की

लापरवाही या लापरवाही से मौत के मामलों को अपने दायरे से बाहर करती है जो किसी भी विवरण की गैर-इरादतन हत्या के बराबर है।"

16. पुनः, नरेश गिरि बनाम एम. पी. राज्य [(2008) 1 एस. सी. सी. 791] के मामले में, जहां एक ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर अपीलकर्ता द्वारा चलाई जा रही बस को टक्कर मार दी थी और बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, इस न्यायालय ने भा.दं.सं. सी. की खंड 304-ए से आरोपों को बदलते हुए कहाः

"7. भा.दं.सं. सी. की खंड 304-ए उन मामलों में लागू होती है जहां मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं है और यह जानकारी नहीं है कि किए गए कार्य से मृत्यु होने की पूरी संभावना है।यह प्रावधान भा.दं.सं. सी. की खंड 299 और 300 के दायरे से बाहर के अपराधों पर निर्देशित है। खंड 304-ए केवल ऐसे कार्यों पर लागू होती है जो जल्दबाजी और लापरवाही वाले होते हैं और सीधे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण होते हैं।लापरवाही और जल्दबाजी खंड 304-ए के तहत आवश्यक तत्व हैं।

8. खंड 304-ए एक विशिष्ट अपराध का वर्णन करती है जहां लापरवाही या लापरवाही से मृत्यु होती है और वह कार्य खंड 299 के तहत गैर-इरादतन हत्या या खंड 300 के तहत हत्या के बराबर नहीं है।यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भीड़ के बीच में मोटर वाहन चलाता है और इस तरह किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, तो यह केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं होगा और यह कार्य गैर-इरादतन हत्या के बराबर होगा।किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई कार्य करना या यह जानना कि कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, गैर-इरादतन हत्या है। जब आशय या ज्ञान अधिनियम की प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है, तो खंड 304-ए को गैर-इरादतन हत्या के गंभीर और अधिक गंभीर आरोप के लिए जगह बनानी होगी।इस

खंड का प्रावधान लापरवाही से गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं है।कोई भी जल्दबाजी या लापरवाहीपूर्ण कार्य जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दंडनीय हो जाता है। दो तत्व जिनमें से या तो या दोनों एक आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए साबित हो सकते हैं, उतावलेपन/लापरवाही हैं; एक व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से मृत्यु का कारण बन सकता है जिसका गाड़ी चलाने से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है।खंड 304-ए के संदर्भ में दंडनीय होने के लिए लापरवाही और जल्दबाजी को मन की उस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसमें निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने के कारण आपराधिकता उत्पन्न होती है, लेकिन मन में अपराध के साथ-साथ उस व्यक्ति के जीवन को जोखिम में डालने के लिए विचार-विमर्श होता है जो अपराध के परिणामस्वरूप अपनी जान गंवा सकता है।खंड 304-ए से पता चलता है कि आपराधिकता यह हो सकती है कि किसी भी पुरुष कारण के अलावा, कोई उद्देश्य या इरादा नहीं हो सकता है, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसी जल्दबाजी या लापरवाही का साहस या अभ्यास कर सकता है जिससे दूसरे की मृत्यु हो सकती है।इस तरह से हुई मौत निर्धारण कारक नहीं है।

9. लापरवाही क्या है, इसका विश्लेषण हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण), खंड में किया गया है। 34, पैरा 1 (पृ. 3), इस प्रकार हैः

"1. लापरवाही के कानून के सामान्य सिद्धांत।—लापरवाही एक विशिष्ट अपराध है और किसी भी परिस्थिति में उस देखभाल का प्रयोग करने में विफलता है जिसकी परिस्थितियाँ माँग करती हैं।लापरवाही क्या है, यह प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।इसमें कुछ ऐसा करना छोड़ना शामिल हो सकता है जिसे किया जाना चाहिए या कुछ ऐसा करना जो या तो अलग तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।जहाँ देखभाल करने का कोई कर्तव्य नहीं है, वहाँ लोकप्रिय अर्थ में लापरवाही का कोई कानूनी परिणाम नहीं है।जहाँ देखभाल करने का कर्तव्य है, वहाँ ऐसे कृत्यों या चूक

से बचने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए जो उचित रूप से व्यक्तियों या संपत्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने की संभावना हो सकती है।विशेष मामले में आवश्यक देखभाल की मात्रा आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और सामना किए जाने वाले जोखिम की मात्रा और संभावित चोट के परिमाण के अनुसार भिन्न हो सकती है। देखभाल का कर्तव्य केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो निकटवर्ती खतरे के क्षेत्र में हैं; यह तथ्य कि प्रतिअभियोक्ता के कार्य ने किसी तीसरे व्यक्ति की देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, अभियोक्ता को दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है जो उसी कार्य से घायल भी है जब तक कि वह भी निकटवर्ती खतरे के क्षेत्र में न हो।उसी कार्य या चूक में तदनुसार कुछ परिस्थितियों में लापरवाही के रूप में दायित्व शामिल हो सकता है, हालांकि अन्य परिस्थितियों में यह ऐसा नहीं करेगा।भौतिक विचार देखभाल की अनुपस्थिति में है जो प्रतिअभियोक्ता की ओर से मामले की परिस्थितियों में अभियोक्ता को देय है और अभियोक्ता को हुए नुकसान के साथ-साथ दोनों के बीच कारण और प्रभाव का एक स्पष्ट संबंध है।"

13. शब्दकोश के अनुसार जिसका अर्थ है "लापरवाह" का अर्थ है "लापरवाह", किसी के कार्यों के संभावित हानिकारक परिणामों की परवाह किए बिना या लापरवाही से।यह अनुमान लगाता है कि यदि कार्य करने वाले द्वारा कार्य किए जाने से पहले इस मामले पर विचार किया गया होता, तो उसके लिए यह स्पष्ट होता कि इसके प्रासंगिक हानिकारक परिणाम होने का एक वास्तविक जोखिम था; लेकिन, यह देखते हुए, लापरवाही मन की सभी स्थितियों को शामिल करती है, जिसमें कोई भी विचार देने में विफल रहने से लेकर उन हानिकारक परिणामों का कोई जोखिम है या नहीं, जोखिम के अस्तित्व को पहचानना और फिर भी इसे अनदेखा करने का निर्णय लेना शामिल है।"

17. मोहम्मद के मामले में।अयनुद्दीन उपनाम मियाम बनाम ए. पी. राज्य [(2000) 7 एस. सी. सी. 72], जिसमें अपीलकर्ता बस चला रहा था और जब एक

यात्री बस में सवार हो रहा था, बस चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप यात्री गिर गया और बस का पिछला पहिया यात्री के ऊपर से चला गया।इस न्यायालय ने जल्दबाजी के कार्य और लापरवाही के कार्य के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह दोषपूर्ण जल्दबाजी और आपराधिक लापरवाही थी और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"7. यह एक गलत धारणा है कि किसी भी मोटर दुर्घटना के लिए चालक की लापरवाही मानी जानी चाहिए।ऐसी प्रकृति की दुर्घटना जो प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि इसे वाहन के चालक की लापरवाही के अलावा किसी और चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, एक अनुमान पैदा कर सकता है और ऐसे मामले में चालक को यह बताना होगा कि उसकी ओर से लापरवाही के बिना दुर्घटना कैसे हुई।केवल इसलिए कि कोई यात्री बस में चढ़ते समय बस से नीचे गिर गया, बस के चालक के खिलाफ लापरवाही का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

9. जल्दबाजी मुख्य रूप से एक अति-जल्दबाजी वाला कार्य है।यह जानबूझकर किए गए कृत्य का विरोध करता है।फिर भी एक जल्दबाजी का कार्य इस अर्थ में एक जानबूझकर किया गया कार्य हो सकता है कि यह उचित देखभाल और सावधानी के बिना किया गया था।दोषपूर्ण जल्दबाजी लापरवाही के साथ और परिणामों के प्रति उदासीनता के साथ एक कार्य करने के जोखिम में निहित है।आपराधिक लापरवाही आम तौर पर जनता या विशेष रूप से किसी व्यक्ति को चोट लगने से बचाने के लिए उचित और उचित देखभाल और सावधानी के साथ कर्तव्य का पालन करने में विफलता है।इस तरह की उचित और उचित देखभाल और सावधानी अपनाना वाहन चालक का अनिवार्य कर्तव्य है।"

18. उपरोक्त के आलोक में, अब हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या दुर्घटना के मामले में लापरवाही परिचर परिस्थितियों से ली जा सकती है।हम पहले ही

मान चुके हैं कि रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत दुर्घटना के मामलों पर समान रूप से लागू होता है न कि केवल नागरिक न्यायशास्त्र पर।इस प्रकार, इन सिद्धांतों को समान रूप से आपराधिक मामलों तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते परिचर परिस्थितियाँ और बुनियादी तथ्य साबित हों।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि या तो दुर्घटना को उचित और ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए या इस सिद्धांत को लागू करने से पहले यह एक स्वीकृत तथ्य होना चाहिए।यह सिद्धांत बाद के चरण में सहायता के लिए आता है जहां यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना कैसे और किसकी लापरवाही के कारण हुई। दुर्घटना का तथ्य स्थापित हो जाने के बाद, न्यायालय उचित साक्ष्य की सहायता से परिचर परिस्थितियों की सहायता ले सकता है और रेज़ इप्सा लोकितुर के सिद्धांत को लागू कर सकता है।दुर्घटना की घटना के मात्र तथ्य का मतलब यह नहीं है कि यह किसी की लापरवाही के कारण होना चाहिए।ऐसे मामलों में जहां लापरवाही प्राथमिक कारण है, यह हमेशा यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है कि यह मौजूद है।ऐसे मामलों में लापरवाही साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं।परिवेशीय साक्ष्य में ऐसे तथ्य होते हैं जो आवश्यक रूप से लापरवाही को एक स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करने के बजाय एक तार्किक निष्कर्ष के रूप में इंगित करते हैं। इस सिद्धांत के तत्वों को इस प्रकार कहा जा सकता हैः

यह घटना किसी की लापरवाही के कारण नहीं हुई होगी। अभिलेख पर साक्ष्य इस संभावना को खारिज करता है कि पीड़ित या किसी तीसरे पक्ष की कार्रवाई घटना के पीछे का कारण हो सकती है। अभियुक्त लापरवाही करता था और पीड़ित की देखभाल करना उसका कर्तव्य था।

19. ठाकुर 9. बनाम पंजाब राज्य [(2003) 9 एस. सी. सी. 208] के मामले में, याचिकाकर्ता ने 41 राहगीरों के साथ लापरवाही से बस चलाई और एक पुल पार करते समय बस पास की नहर में गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी यात्रियों की

मौत हो गई।न्यायालय ने रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को लागू किया क्योंकि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर बस चला रहा था और जब वह नीचे गिरा तो वह पुल के ऊपर से जा रही थी।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"4. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता स्वयं संबंधित समय पर वाहन चला रहा था।यह भी स्वीकार किया जाता है कि बस को एक पुल के ऊपर से चलाया गया और फिर वह नहर में गिर गई।ऐसी स्थिति में रेस इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत लागू हो जाता है और यह स्थापित करने के लिए कि दुर्घटना उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण नहीं हुई थी, बोझ उस व्यक्ति पर चला जाता है जो ऑटोमोबाइल के नियंत्रण में था।वह यह दिखाने में सफल नहीं हुए कि दुर्घटना उनकी ओर से लापरवाही के अलावा अन्य कारणों से हुई थी।"

20. फिर भी, मोहम्मद के मामले में।अयनुद्दीन (ऊपर), इस न्यायालय ने यह सिद्धांत भी कहा हैः

"8. रेज़ इप्सा लोकिटुर का सिद्धांत लापरवाही से संबंधित कार्यों में सबूत की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए केवल सबूत का एक नियम है।उक्त सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब दुर्घटना की प्रकृति और उपस्थित परिस्थितियों से यथोचित रूप से यह विश्वास होगा कि लापरवाही की अनुपस्थिति में में दुर्घटना नहीं हुई होगी और जो चीज चोट पहुंचाती है वह कथित अपराधी के प्रबंधन और नियंत्रण में दिखाई देती है"

21. यह भी कहा गया है कि इस सिद्धांत का प्रभाव, हालांकि, निकाले जाने वाले निष्कर्षों की दृढ़ता पर निर्भर करता है और इसलिए, प्रत्येक मामले में अलग-अलग होना चाहिए।इन सिद्धांतों के आलोक में, आइए हम वर्तमान मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करें।यह तर्क दिया गया है कि यह दिखाने के लिए सबूत

का एक टुकड़ा भी नहीं है कि या तो आरोपी वाहन चला रहा था या, जैसा कि आरोप लगाया गया है, वह उतने ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।संबंधित पुलिस अधिकारी ने सुखदेव का 'परचा बयान' (प्रदर्शनी पी2) दर्ज किया था, जिससे अदालत में पी. डब्ल्यू2 के रूप में पूछताछ की गई थी।इस बयान को आगे बढ़ाते हुए, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी।इस दस्तावेज़ में कहा गया था कि 20 अप्रैल, 1991 को सुखदेव अपने बहनोई की शादी में शामिल होने के लिए जीप में बैठकर अलवर से गोविंदगढ़ जा रहे थे।लगभग 9.15 पूर्वाहन वे बागड़ तिराया के क्रॉसिंग के पास पहुंचे, उस जीप के आगे एक जीप आर. एन. ए. 638 थी जिसमें उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य यात्रा कर रहे थे।एक और मारुति वैन उस जीप के आगे चल रही थी।एक बस आर. एन. ए. 339 बागगढ़ की ओर से तेज गति से आ रही थी। मारुति वैन, जिसने खुद को बचा लिया था, किनारे पर ले गई और यात्रियों को मारने के इरादे से बस का चालक जीप आर. एन. ए. 638 से टकरा गया।चेत कौर, रिंकी, गीता और चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी की हालत गंभीर थी, यानी, निरंजन सिंह, लाहौरी सिंह, कैलाश, वेंतो और टिंकू।उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के समय, बस को रवि कुमार (कपूर) चला रहे थे, जिनकी पहचान राहगीरों द्वारा की गई, जिन्होंने सुखदेव को उनका नाम बताया।उसके साथ जीप में बैठे अन्य लोगों ने भी बस चालक की पहचान की।चालक वाहन को सड़क पर गड्ढे के नीचे खड़ा कर फरार हो गया।पीडब्लू2 के रूप में उसकी जाँच करने पर, इस गवाह ने कहा कि मारुति वैन कच्छा सड़क के किनारे उतर गई और यहां तक कि उनकी अपनी जीप को भी कच्छा की ओर खींचा गया, लेकिन तीसरी जीप सामने की ओर से बस से टकरा गई।उन्होंने पहचान की कि अदालत में आरोपी व्यक्ति स्वयं बस चला रहा था और परचा बयान (बयान), प्रदर्शनी पी2 में अपने बयान की पुष्टि की।उनसे विस्तृत जिरह की गई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जीप में बैठे हुए बस चालक को नहीं

देखा, हालांकि उन्होंने आरोपी को बस से उतरते हुए देखा था और यह तथ्य उनके बयान (प्रदर्शनी पी2) में नहीं था क्योंकि उन्हें याद नहीं था।राहगीरों ने उसे चालक का नाम बताया था जो प्रदर्शनी पी2 में दर्ज था।उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी पी3, स्थल योजना, उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी और उनके हस्ताक्षर अस्पताल में प्राप्त किए गए थे।

22. पीडब्लू1, सुश्री शीला गुप्ता ने बताया कि जोगा सिंह और उनके रिश्तेदार उस वाहन के आगे एक अन्य वाहन में जा रहे थे जिसमें वह यात्रा कर रही थीं।यह बस से टकरा गई।वह बेहोश थी और उसने किसी को या बस के चालक को नहीं देखा।

23. पीडब्लू 3, सुभाष चावला ने अपनी जाँच में दुर्घटना को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें बस के चालक का नाम नहीं पता था और यह भी कि उनके पीछे की जीप हॉर्न बजा रही थी और जैसे ही बीच में जीप पहुंची, दुर्घटना हो गई।उन्हें शत्रु घोषित कर दिया गया था।

24. पीडब्लू4, मुल्तान सिंह ने भी इसी तरह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार तथ्यों को बताया है।उन्होंने कहा कि वह दूसरी जीप में बैठे थे।उनके अनुसार, बस दिल्ली रोड के किनारे से तेज गति से आई थी।यह एक निजी बस थी और इसने जीप को टक्कर मार दी।बस गलत दिशा से आ रही थी और जीप के सामने से टकरा गई।उसके सिर और पीठ पर भी चोटें आई हैं।जब वह नीचे उतरा और खड़ा हुआ तो उसने चालक को भागते देखा।हालाँकि वह घायल हो गया था, लेकिन उसने ड्राइवर को देखने का दावा किया और पुष्टि की कि उक्त ड्राइवर अदालत में मौजूद था और उसने आरोपी की पहचान की। अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि टक्कर पर, उन्होंने पटाखे फोड़ने जैसी आवाज सुनी।

25. पीडब्लू11, सोहन लाल, जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए 'परचा बयान' लिखने की पुष्टि की, जिसके लिए वह साइट पर आगे बढ़े और उसके बाद भा.दं.सं. की खंड 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने स्थल योजना तैयार की, घटना स्थल का पी29/पी3 प्रदर्शित किया, जांच रिपोर्ट तैयार की और जब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी पी31 के माध्यम से बस No.RNA 339 और जब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी पी32 के माध्यम से जीप को जब्त कर लिया।अपनी जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि घटना का स्थान एक मोड़ था।उन्हें याद नहीं था कि जीप बस के सामने से टकराई थी या नहीं और यह प्रदर्शनी पी32 में दर्ज नहीं था कि जीप के किस हिस्से ने बस को टक्कर मारी थी।उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि चालक रवि कपूर मौके पर मौजूद था या नहीं। मुझे नहीं पता कि बस के यात्री वहाँ थे या नहीं।लेकिन बस वहाँ थी।मैंने यात्रियों से पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन वे पहले ही जा चुके थे।परीक्षण 25 पृष्ठ 26 अभियुक्त की पहचान घायलों से नहीं की गई क्योंकि मौके पर मौजूद सभी लोगों ने मुझे अभियुक्त के बारे में पहले ही बता दिया था।

26. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं और साइट योजना प्रदर्शनी पी29/पी3 अपीलकर्ता की ओर से कोई लापरवाही नहीं दिखाती है।अपीलकर्ता दुर्घटना में शामिल वाहन नहीं चला रहा था और इसलिए वह दोषमुक्ति का हकदार है।

27. हम इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं।सबसे पहले, बस को ज़ब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी पी31 के माध्यम से जब्त कर लिया गया और बाद में बस के मालिक यानी आरोपी को सुपरदारी पर दे दिया गया।यह बस निश्चित रूप से दुर्घटना में शामिल थी, वास्तव में, हमारे सामने कोई गंभीर विवाद नहीं है कि जीप आरएनए 638 और बस

आरएनए 339 के बीच दुर्घटना घटना स्थल पर हुई थी।यदि कोई प्रदर्शनी पी29/पी3 की जांच करता है, तो यह स्पष्ट है कि यह एक संकीर्ण सड़क थी जो लगभग 18 फीट चौड़ी थी और दुर्घटना सड़क के एक मोड़ पर हुई थी।दुर्घटना प्वाइंट 8 पर हुई।जिस जीप में कई लोगों की मौत हुई, वह बिंदु XA पर या उसके आसपास तैनात रही, जबकि बिंदु 8 मिट्टी के विभाजक (डम्बंड) को दर्शाता है, दुर्घटना बिंदु 1 और बिंदु 8 पर हुई थी जहां बस खड़ी की गई थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दुर्घटना के बाद बस को स्थानांतरित कर दिया गया था।रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक गंभीर दुर्घटना थी जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।दुर्घटना के बाद बस चालक ने बस को दूसरी जगह ले जाया।यदि अपीलकर्ता की ओर से जो प्रस्तुत किया गया है, उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो बस चालक का सबसे उचित आचरण यह दिखाना होगा कि वह वाहन को दुर्घटना स्थल पर छोड़ दे ताकि यह दिखाया जा सके कि वह सड़क के सबसे बाईं ओर (गाड़ी चलाने के लिए उसकी दाहिनी ओर) था और जो जीप दूसरे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, वह सड़क के गलत तरफ आ गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।यह एक बहुत ही भौतिक परिस्थिति और चालक का प्रासंगिक आचरण होता।

28. सभी गवाहों, पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने ऐसा कहा है।गवाहों के बयान में एकरूपता है कि आरोपी वाहन चला रहा था और घटना स्थल से दूर एक स्थान पर वाहन खड़ा करने के बाद वह भाग गया था।हमारे पास इन गवाहों के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्शनी पी 2 द्वारा समर्थित हैं, जिसके लिए पीडब्लू 11 के क्रॉससेक्सैमिनेशन के दौरान शायद ही कोई चुनौती थी।हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में किसी भी गंभीर या भौतिक विरोधाभास को देखने में असमर्थ हैं, पी. डब्ल्यू. 2 के परचा बयान, प्रदर्शनी पी.

2 में बहुत कम।जब घटना की तारीख से काफी समय बीत जाने के बाद गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं तो उनके बयानों में मामूली बदलाव होना तय है।अदालत इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि ये गवाह बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं। गवाहों की सच्चाई इस तथ्य से भी प्रदर्शित होती है कि पीडब्लू1 ने अपने मुख्य परीक्षण में भी कहा कि वह बेहोश थी और उसने चालक को नहीं देखा था।कुछ भी उसे यह बयान देने से नहीं रोक सका कि उसने वास्तव में आरोपी को देखा था।इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि तीन गवाहों, यानी पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने दुर्घटना का सही विवरण दिया है। हम उनके बयानों को विश्वास के योग्य पाते हैं और अदालत के लिए इन गवाहों पर अविश्वास करने का कोई अवसर नहीं है। यह एक तय सिद्धांत है कि गवाहों के बयानों में भिन्नताएं जो न तो सामग्री हैं और न ही अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं, उन्हें अदालतों द्वारा नजरअंदाज किया जाना चाहिए।{रेफ. राज्य बनाम सरवनन और अन्र। [(2008) 17 एस. सी. सी. 587]; और सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2010 13 एस. सी. सी. 657]]।यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि गवाहों के बयानों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और न्यायालय को पूरे बयान से अलग एक सजा नहीं लेनी चाहिए और इसके उचित संदर्भ को नजरअंदाज करते हुए, एक पक्ष के खिलाफ या पक्ष में इसका उपयोग करना चाहिए।विरोधाभासों को सारवान और सारवान होना चाहिए ताकि अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।इस संबंध में आत्माराम और अन्य का संदर्भ दिया जा सकता है।मध्य प्रदेश राज्य [(2012) 5 एस. सी. सी. 738]

29. नागेश्वर श्री कृष्ण घोबे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 4 एस. सी. सी. 23] के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले गवाहों या पास में चलाए गए वाहन में यात्रा कर रहे लोगों के बयानों को

उनके सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वाहन में सवार लोग उसी दिशा में देख रहे हों।हो सकता है कि वे केवल शोर या दुर्घटना के परिणामस्वरूप वास्तविक प्रभाव के कारण होने वाली गड़बड़ी से आकर्षित हुए हों।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"6. तेजी से चलने वाले वाहनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में आम तौर पर ऐसे गवाहों को ढूंढना मुश्किल होता है जो वास्तविक दुर्घटना से तुरंत पहले के कुछ क्षणों के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के अनुक्रम की सकारात्मक पुष्टि करने की स्थिति में हों, जिससे इसके वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके।जब सड़क पर दुर्घटनाएँ होती हैं, तो सड़क का उपयोग करने वाले लोग या जो आस-पास हो सकते हैं, वे आम तौर पर अपने पूर्व-व्यवसायों में व्यस्त होते हैं और सामान्य रूप से उनका ध्यान केवल शोर या दुर्घटना के परिणामस्वरूप वास्तविक प्रभाव से होने वाली गड़बड़ी से आकर्षित होता है। तभी वे शोर की दिशा की ओर देखेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था। यह शायद ही कभी होता है-और यह केवल संयोग की बात है-कि कोई व्यक्ति पहले से ही दुर्घटना की दिशा में देख रहा होगा और उस कारण से उन घटनाओं के अनुक्रम को देखने और बाद में वर्णन करने की स्थिति में हो सकता है जिसमें दुर्घटना हुई थी।कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आकस्मिक रूप से घटना को देखने के बाद वे व्यक्ति इस मामले में कोई और रुचि लेने के लिए अनिच्छुक महसूस कर सकते हैं, चाहे इस अनिच्छा का कारण कुछ भी हो। हालाँकि, यदि वे कुछ और जानने की अपनी जिज्ञासा में उस स्थान पर जाने में रुचि महसूस करते हैं, तो वे वहाँ क्या देख सकते हैं, उन्हें कुछ राय या धारणा बनाने के लिए प्रेरित करेगा कि दुर्घटना का कारण क्या होना चाहिए।इसलिए, ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा और उनके कल्पनाशील अनुमान का परिणाम क्या हो सकता है। चश्मदीद गवाहों के अलावा, एकमात्र व्यक्ति जिसे वास्तव में

संतोषजनक रूप से समझाने में सक्षम माना जा सकता है कि वर्तमान जैसी दुर्घटनाओं की परिस्थितियों के बारे में ड्राइवर स्वयं या कुछ परिस्थितियों में कुछ हद तक घायल व्यक्ति है। वर्तमान मामले में दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सबूत देने के लिए उपलब्ध नहीं है।भैय्या (हरबनसिंह) को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है।वास्तव में, इस मामले में उन्हें पेश करने में विफलता श्री पारदीवाला द्वारा हमले का प्रमुख आधार रही है और उन्होंने अभियोजन पक्ष की ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ-साथ अन्य गवाहों द्वारा दिए गए बयान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया है।"

30. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, मुल्ला और अन्न के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए।उत्तर प्रदेश राज्य [(2010) 3 एस. सी. सी. 508] और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 107] ने तर्क दिया कि किसी भी गवाह ने वास्तव में आरोपी को वाहन चलाते हुए नहीं देखा था और इसलिए, परीक्षण पहचान परेड की अनुपस्थिति में में, यह माना जाना चाहिए कि आरोपी वाहन नहीं चला रहा था और उसकी पहचान नहीं की गई थी।मुल्ला (उपरोक्त) के मामले में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए जाने पर, अदालत ने कहा था कि यह वांछनीय है कि गवाहों की ओर से किसी भी गलती से बचने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए।

31. दूसरी ओर, इस निवेदन का विरोध करने के लिए, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने मायलादिम्मल सुरेंद्रन अन्य अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।केरल राज्य [(2010) 11 एस. सी. सी. 129] का कहना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में परीक्षण पहचान परेड आवश्यक नहीं थी और किसी भी मामले में आरोपी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है और परीक्षण पहचान परेड का आयोजन हमेशा आवश्यक नहीं है।

32. वर्तमान मामले में आरोपी को पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने देखा था।इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा था कि राहगीरों ने उन्हें सूचित किया था कि आरोपी बस चला रहा था और वास्तव में, वह बस का मालिक था।इस कथन का एक तथ्य यह स्थापित होता है कि विचाराधीन बस अभियुक्त को सुपरदारी पर दी गई थी।इन व्यक्तियों द्वारा यह भी कहा गया है कि अभियुक्त को देखने के बाद वह उस स्थान से भाग गया था जहाँ उसने वाहन खड़ा किया था।इन गवाहों ने अदालत में अभियुक्तों की पहचान भी की।यह हमारे सामने आरोपी का मामला नहीं है कि अदालत में उसकी पहचान होने से पहले उसे गवाहों को दिखाया गया था।अदालत की पहचान अपने आप में कानून की नजर में एक अच्छी पहचान है।यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि यह परीक्षण पहचान परेड से पहले होना चाहिए।यह हमेशा किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।एक मामले में, परीक्षण पहचान परेड आयोजित करना भी आवश्यक नहीं हो सकता है, जबकि दूसरे में, ऐसा करना आवश्यक हो सकता है।इस प्रकार, इस संबंध में कोई सीधा जैकेट सूत्र नहीं कहा जा सकता है।हम श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2012 (6) स्केल 381] के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "Cr.P.C) जांच एजेंसी को बिना किसी अपवाद के परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं करती है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"55. अभियुक्त श्यामल की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पहचान परेड आयोजित होने के बावजूद, गवाहों द्वारा उसकी पहचान नहीं की गई थी और यह भी कि पहचान परेड अनुचित देरी के बाद आयोजित की गई थी और तब भी जब घटना के बारे में विवरण पहले ही टेलीविजन पर प्रसारित किया जा चुका था।इस प्रकार, न्यायालय को अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के रूप में अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

56. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का पूरा विचार यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, उन्हें बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करनी है।परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जाँच चरण के दौरान एक पहचान परेड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य, पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

57. यह भी उतना ही सही है कि सी. आर. पी. सी. जांच एजेंसी को अनिवार्य रूप से परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं करती है।पुलिस हिरासत में रहते हुए परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता, अपने आप में अदालत में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य या अस्वीकार्य नहीं बनाती है।ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अदालत में पहली बार गवाहों द्वारा आरोपी की पहचान की गई है।लिए गए विचारों में से एक यह है कि पहली बार अदालत में पहचान अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है, लेकिन यह एक आत्यन्तिक नियम नहीं है। परीक्षण पहचान परेड का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और उसे मजबूत करना है।तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर अदालत में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है, जो पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में है। विवेक का यह नियम हालांकि अपवादों के अधीन है।मुंशी सिंह गौतम बनाम एम. पी. राज्य [(2005) 9 एस. सी. सी. 631], शिव शंकर सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्न का संदर्भ दिया जा सकता है। [(2011) 3 एससीसी 654]।

58. पहचान परेड जांच का एक साधन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से एक ओर अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने और यह दोगुना सुनिश्चित करने के

लिए किया जाता है कि मामले में नामित व्यक्ति वास्तव में अपराधी हैं।पहचान परेड मुख्य रूप से पुलिस द्वारा जांच के चरण से संबंधित है।यह तथ्य कि एक विशेष गवाह एक पहचान परेड में आरोपी की पहचान करने में समर्थ रहा है, केवल अदालत में पहचान की पुष्टि करने वाली एक परिस्थिति है।इस प्रकार, यह केवल एक प्रासंगिक विचार है जिसकी अदालत द्वारा अन्य परिचर परिस्थितियों और किसी दिए गए मामले के तथ्यों के संदर्भ में पुष्टि करने वाले साक्ष्य को देखते हुए जांच की जा सकती है।"

33. हमारे सुविचारित विचार में, दो कारणों से अपीलकर्ता की परीक्षण पहचान परेड आयोजित करना आवश्यक नहीं था।सबसे पहले, अपीलकर्ता उन राहगीरों को पहले से ही जानता था जिन्होंने उसे बस चलाते समय पहचाना था और उसका नाम बताया था और दूसरा, उसे विधिवत देखा गया था, हालांकि एक छोटी लेकिन उचित अवधि के लिए, जब बस खड़ी करने के बाद, वह बस से उतर गया और भाग गया।

34. समान रूप से योग्यता के बिना अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क है कि न्यायालय को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी ने वाहन के मालिक को अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस नहीं दिया था।उच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर सही ही खारिज कर दिया है कि वाहन के चालक की पहचान घटना स्थल पर की गई थी और यहां तक कि राहगीरों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सूचित किया था कि चालक रवि कपूर वाहन का मालिक था।प्राथमिकी आर. में ही अभियुक्त का नाम विधिवत दर्ज किया गया था।यह तथ्य निर्विवाद बना रहा। कुछ जोर देने के साथ, हमारे सामने यह भी तर्क दिया गया कि वह वाहन नहीं चला रहा था, हालांकि यह विवादित नहीं था कि वह विचाराधीन वाहन का पंजीकृत मालिक है।यदि ऐसा है, तो जब निचली अदालत द्वारा Cr.P.C की खंड 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था, तो इनकार के अलावा, उसने आगे कुछ नहीं कहा।अभियुक्त को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, यह बताने

के बजाय कि उसने उस तारीख को अपना वाहन चलाने के लिए किसे दिया था, उसने चुप रहना पसंद किया और अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार कर दिया।

35. यह सच है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है, लेकिन खंड 313 के प्रावधान केवल औपचारिकता या उद्देश्यहीन नहीं हैं। उनका दोहरा उद्देश्य है, पहला, कि दोषारोपण करने वाले साक्ष्य के पूरे भौतिक भागों को कानून के अनुसार अभियुक्त के सामने रखा जाना चाहिए और दूसरा, अभियुक्त को अपने आचरण या मामले के अपने संस्करण को समझाने का अवसर प्रदान करना। अभियुक्त को यह अवसर प्रदान करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है। यदि अभियुक्त जानबूझकर इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहता है, तो कानूनी परिणामों का पालन करना होगा, विशेष रूप से जब आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम में अभियुक्त से कुछ तथ्यों का खुलासा करने की उम्मीद की जाएगी जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी में हो सकते हैं और जिनका मामले पर असर हो सकता है।

36. हमारे सुविचारित विचार में, अधिनियम की खंड 133 के तहत नोटिस न देने से अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा हुआ है और किसी भी मामले में, अभियुक्त इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता है।

37. अंत में, हम अभियुक्त की ओर से उठाए गए पहले विवाद पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपील न्यायालय आम तौर पर दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा, लेकिन यह एक आत्यन्तिक नियम नहीं है और इसमें कई अच्छी तरह से स्वीकृत अपवाद हैं।उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बन्न और अन्र के मामले में। [(2009) 4 एस. सी. सी. 271], न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय भी उच्च न्यायालय के दोषमुक्ति किए जाने के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित होगा, लेकिन केवल तभी जब उच्च न्यायालय

के निर्णय को अस्वीकार करने के लिए बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण हों।हरियाणा राज्य अन्य शकुंतला और अन्य के मामले में। [2012 (4) स्केल 526], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"36. उच्च न्यायालय ने कुछ अभियुक्तों द्वारा ली बहाना याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया है।दोषमुक्ति जाने के फैसले के खिलाफ, अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा सुधार की आवश्यकता है।इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।पहला, ऐसे अभियुक्त के लिए आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों के तहत निर्दोषता का अनुमान उपलब्ध है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अदालत के समक्ष दोषी साबित न हो जाए और दूसरा, कि एक निचली अदालत ने सभी साक्ष्यों की उचित सराहना करने पर उसकी निर्दोषता के पक्ष में पाया है।केवल इसलिए कि एक अन्य दृष्टिकोण संभव है, इस न्यायालय के लिए दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होगा।

37. एल. आर. एस. बनाम द्वारा गिरजा प्रसाद (मृत) में।एम. पी. राज्य [(2007) 7 एस. सी. सी. 625], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"28. उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के फैसले को दरकिनार करने के संबंध में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कुंजू मुहम्मद बनाम केरल राज्य (2004) 9 एस. सी. सी. 193, काशी राम बनाम एम. पी. राज्य ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2902 और मीना बनाम महाराष्ट्र राज्य 2000 सी. आर. आई. एल. जे. 2273 पर भरोसा

किया।हमारी राय में, कानून अच्छी तरह से स्थापित है।दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील भी संहिता के तहत एक अपील है और एक अपील न्यायालय के पास अपने समक्ष साक्ष्य की पुनः सराहना, समीक्षा और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान है और यह अनुमान निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के आदेश से पुष्ट होता है।लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।यह अपील न्यायालय का दायित्व है कि वह कानून के सुसंगत सिद्धांतों को ध्यान में रखे, साक्ष्य की समग्र रूप से पुनः मूल्यांकन करे और आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप ऐसे साक्ष्य पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे।"

38. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [(2007) 4 एस. सी. सी. 415] मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैंः

(1) अपील न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित किया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपील न्यायालय तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई शर्त नहीं लगाता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ",

आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपील न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, एक अपील न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है।सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत निर्दोष होने का अनुमान उसके लिए उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता।दूसरा, अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपील न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।"

39. सी. एंटनी बनाम के. जी. राघवन नायर [(2003) 1 एस. सी. सी. 1] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

"6. इस न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अपील न्यायालय को उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है जिन पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित किया गया है, फिर भी दोषमुक्ति के मामले में ऐसी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपील न्यायालय को न केवल तथ्य के प्रश्न और अपने दोषमुक्ति के आदेश के समर्थन में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दिए गए कारणों से संबंधित

प्रत्येक मामले पर विचार करना चाहिए, बल्कि उसे निर्णय में अपने कारणों को व्यक्त करना चाहिए जिसके कारण उसे यह अभिनिर्धारित करना पड़ा कि दोषमुक्ति उचित नहीं है। उन मामलों में इस निचली अदालत ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अपील न्यायालय को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि निचली अदालत को गवाहों को गवाह पेटी में देखने का लाभ मिला था और निर्दोष होने की धारणा दोषमुक्ति के आदेश से कमजोर नहीं होती है, और ऐसे मामलों में यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है, तो अपील न्यायालय को निचली अदालत के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए।(भीम 9. रूप 9. बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 और धर्मदेव 9. बनाम बिहार राज्य देखें।)"

40. राज्य उपरोक्त तय किए गए सिद्धांतों के लिए अपवाद का मामला नहीं समर्थ पाया है।यह राज्य को दिखाना था कि उच्च न्यायालय पूरी तरह से कानून की त्रुटि में पड़ गया है या इन अभियुक्तों के संबंध में निर्णय स्पष्ट रूप से गलत, विकृत या असमर्थनीय था। तीन अभियुक्तों को दोषमुक्ति जाने के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील में इनमें से कोई भी मानदंड संतुष्ट नहीं है।"

38. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के पास निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति जाने के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण हैं। संभवतः, इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया था और इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय के फैसले में शायद ही कोई कारण दर्ज किए गए हैं।चाहे जो भी हो, यह साक्ष्य की अनुपलब्धता या सामग्री की उपस्थिति और अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित होने वाले गंभीर विरोधाभासों का मामला नहीं था। पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा दिए गए नेत्र विवरण पर विश्वास न करने के लिए निचली अदालत के समक्ष कोई प्रशंसनीय कारण नहीं था और अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि आरोपी की घटना के स्थान

पर और यहां तक कि अदालत में भी विधिवत पहचान की गई थी।निचली अदालत निश्चित रूप से कानून की त्रुटि और साक्ष्य की प्रशंसा में पड़ गया है।एक बार जब निचली अदालत साक्ष्य के भौतिक अंश को नजरअंदाज कर देता है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अपने सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो यह न्यायाधीश की विफलता होगी। कुछ मामलों में, साक्ष्य के मूल्यांकन में ऐसी त्रुटि विकृत निष्कर्षों को दर्ज करने के बराबर भी हो सकती है।हम यह भी देख सकते हैं कि पुनरावृत्ति की कीमत पर निचली अदालत ने पहली बार 24 जून, 1999 को अपराधों के अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अपना निर्णय दिया था।हालाँकि, अपील पर, मामले को दो आधारों पर रिमांड पर लिया गया था, अर्थात, परीक्षण पहचान परेड का आयोजन न करने और डॉक्टर की जांच न करने के प्रभाव पर विचार करते हुए।रिमांड पर आने पर निचली अदालत ने पहले की तुलना में अलग दृष्टिकोण अपनाया था और 11 मई, 2006 के फैसले में उसने आरोपी को बरी कर दिया था।यह स्वयं निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति जाने के फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आधार बन गया।निचली अदालत के फैसले से, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के न होने या डॉक्टर की परीक्षा न होने के प्रभाव पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं होती है। इसके विपरीत, निचली अदालत ने कुछ धारणाओं पर अपना फैसला सुनाया। किसी भी गवाह, यहां तक कि आरोपी ने भी अपने बयान में यह नहीं कहा था कि जीप तेज गति से चल रही थी, लेकिन फिर भी निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि जीप तेज गति से चल रही थी और उसे ठीक से नहीं चलाया जा रहा था।निचली अदालत ने यह भी दर्ज किया कि इस बात का संदेह पैदा होता है कि दुर्घटना के समय रवि कपूर वास्तव में बस चला रहे थे या नहीं और पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी।

39. हम यह समझने में असमर्थ हैं कि निचली अदालत कैसे चश्मदीद गवाहों के बयान को नजरअंदाज कर सकती है, विशेष रूप से जब वे विश्वसनीय, भरोसेमंद थे और उन्होंने दुर्घटना का सबसे उपयुक्त नेत्र विवरण दिया था।अतः निचली अदालत के निर्णय में विधि की त्रुटियाँ और साक्ष्य दोनों की सराहना की गई।निचली अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने के फैसले में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप किसी भी अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

40. पूर्व में दर्ज किए गए कारणों से, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।उसी के अनुसार खारिज कर दिया जाता है।

के. के. टी. अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।